इकाई 8 औद्योगीकरण 1851-1914*

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 फ्रांस : औद्योगिक पूँजीवाद 1848-70

8.3 औद्योगिक पूँजीवाद का विकास 1871-1914

8.4 जर्मनी : परिवर्तन के स्रोत

- 8.4.1 नेपोलियन युग के विधान
- 8.4.2 जोल्विरेन
- 8.4.3 रेलवे
- 8.4.4 संयुक्त पूँजी बैंकों का विकास

8.5 1871 के बाद विकास

8.6 रूसी औद्योगीकरण में राज्य की भूमिका

8.7 गेरशेनक्रोन प्रारूप

8.8 औद्योगिक प्रवृत्तियां : 1860 के दशक से 1890 के दशक तक

8.9 विट व्यवस्था

- 8.9.1 तीव्र वृद्धि
- 8.9.2 राजस्व और कराधान
- 8.9.3 विदेशी पूँजी की भूमिका
- 8.9.4 1890 के दशक में तेज औद्योगिक विकास का मूल्यांकन

8.10 1901 से 1914 तक औद्योगिक पूँजीवाद

- 8.10.1 संकट
- 8.10.2 एकाधिकार स्थापित करने के तरीके
- 8.10.3 1908-13 में हुआ विकास
- 8.10.4 1914 में रूस

8.11 सारांश

8.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- यह समझ सकेंगे कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में फ्रांस, जर्मनी तथा रूस जैसे देशों में औद्योगिक पूँजीवाद का विकास किस प्रकार हुआ;
- यह जान सकेंगे कि कैसे इस औद्योगीकरण में राज्य ने पहले के इंग्लैण्ड के औद्योगीकरण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई;

*डॉ. हरि वासुदेवन (रिटायर्ड), डिपार्टमेंट ऑफ मॉर्डन इंडियन हिस्ट्री, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता एवं प्रो. अरूप बनर्जी (रिटायर्ड), डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

- यह समझ सकेंगे कि कैसे कई सीमाओं के बावजूद रूसी उद्योग अधिक तेज़ विकास कर पाया; और
- जान सकेंगे कि उपयोगता वस्तुओं की सीमित माँग होने के कारण किस प्रकार औद्योगिक विकास का केन्द्र बिन्दु भारी उद्योग बना।

8.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई (इकाई 7) में हमने अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में औद्योगीकरण की प्रगति की चर्चा की। इस इकाई में अब हम इसके आगे अर्थात् उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के बाद के काल में औद्योगिक पूँजीवाद के विकास का अध्ययन करेंगे। जर्मनी, फ्रांस और रूस में औद्योगीकरण उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में इंग्लैण्ड में हुआ था। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि 1850 के पश्चात इन देशों में औद्योगीकरण का विकास किस प्रकार हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के इंग्लैण्ड की परिस्थितियों से बिल्कुल विपरीत कुछ विशेषताओं को इंग्लैण्ड के बाहर देरी से औद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी माना गया। फ्रांस, जर्मनी और रूस ने औद्योगिक विकास के रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना किस प्रकार किया, इस इकाई की चर्चा का केन्द्र बिन्दु होगा। साथ-साथ इन देशों में औद्योगिक पूँजीवाद के विकास की भी चर्चा की जाएगी।

8.2 फ्रांस : औद्योगिक पूँजीवाद 1848-70

फ्रांस में 1847-51 की गंभीर मंदी के बाद फ्रांसीसी उद्योग में निश्चित विकास देखने को मिला। इसलिए कई लोग यह मानते हैं कि फ्रांस में औद्योगीकीकरण 1850 के बाद प्रारंभ हुआ। यह 1848 की क्रांतियों के बाद पूरे यूरोप में सोने की उपलब्धता और लगभग 1860 तक रेलवे में हुए तीव्र विकास का परिणाम था कि कपड़ा, कोयला और रेलवे जैसे प्रमुख विकास के क्षेत्रों में फ्रांस में भारी पूँजी का निवेश संभव हुआ। इसके परिणामस्वरूप फ्रांसीसी उद्योग में जल-शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति का इस्तेमाल किया जाने लगा और लौह उत्पादन के लिए लकड़ी के कोयले के स्थान पर कोयला आधारित लौह प्रगलन द्वारा उत्पादन होने लगा। इस अवधि में नॉर पैकल्ले (Nord, Pas De Calais) के कोयला भंडारों से खूब कोयला निकाला गया जो इस समय ईंधन का प्रमुख स्रोत हो गया था, हालांकि यह प्रगलन (लोहे को गलाने) के लिए बहुत उपयोगी नहीं था क्योंकि यहाँ कोक नहीं निकलता था। 1852 में कोयले का कुल राष्ट्रीय उत्पाद् 5,000,000 मेट्रिक टन था जिसमें 1,000,000 मेट्रिक टन का उत्पादन नार्थ बेसिन से उपरी लुयर से 1,640,000 मेट्रिक टन (लू क्रुजो और ब्लेन्जी से 400,000 मेट्रिक टन तथा शेष अन्य छोटी खदानों से निकाला जाता था।) 1869 में राष्ट्रीय उत्पादन 13,000,000 मेट्रिक टन था जिसमें उत्तरी हिस्से में 4,300,000 और ऊपरी लुयर में 3,100,000 मेट्रिक टन कोयले का उत्पादन होता था। अन्य स्थानों में ढलवाँ लौहे का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा (1853 में 600,000 टन से बढ़कर 1869 में 1,400,000 टन हो गया); बेसेमर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए 1869 में इस्पात उत्पादन 1,000,000 टन हो गया और अन्तरराष्ट्रीय उत्पादन में ब्रिटेन के बाद इसका दूसरा स्थान हो गया। उत्पादन के मुख्य केंद्र सेंटइतेन (टेर न्यू आर कंपनी और पेटेन गुडेट का उद्यम), लू क्रूजो (श्नाईडर उद्यम), लॉरेन में (द वेन्डल के विभिन्न उद्यमों में) और अल्जास में निडरब्रौन में (डियेटरिस उद्यम में) स्थित था। कमेंट्री और फोरशेग्बों (बेल्ज़ियन सीमा पर) और उत्तर में ऐजिन और डेनेन स्थित कंपनियों में लोहे का उत्पादन होता था।

सूती कपड़ा उद्योग में, नॉरमेंडी और लिल्ल जिले में (जहाँ 1860 के दशक तक तथा उसके बाद भी कताई होती थी) उत्पादन यथावत रहा परंतु 1870 तक आते-आते अल्जास में सूती

उद्योग का मशीनीकरण और परिष्करण लैंकाशायर के स्तर तक पहुँच गया। अल्जास में ऊर्जा से चलने वाली मशीनों का विकास किया गया जो इंग्लैंड की मशीनों का मुकाबला कर सकती थी; जो बात सूती कपड़ा उद्योग पर लागू होती थी वही ऊनी कपड़ों पर भी लागू होती थी क्योंकि उस समय इस उद्योग का विस्तार ऑस्ट्रेलियाई कच्चे ऊन के आयात पर निर्भर करता था।

इस अवधि में उत्पादन में हुई वृद्धि पर अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों का तो प्रभाव पड़ा ही परंतु इस अवधि में द्वितीय साम्राज्य के तहत बोनापार्टिस्ट राज्य के हस्तक्षेप से इस दिशा में तीव्र प्रगति हुई। नेपोलियन-III के सेंट सिमोनियम सिद्धांतों से विकास को प्रोत्साहन मिला। इसी दौरान क्रेडिट फोन्सियर (एक राष्ट्रीय ऋण बैंक) और क्रेडिट मोबिलियर (पेरिरे बंधुओं के संयुक्त पूँजी बैंक) की स्थापना सरकार की सहायता द्वारा की गई। दोनों बैंकों की स्थापना नेपोलियन के राष्ट्राध्यक्ष (प्रेसिडेंट) बनने के तुरंत बाद हुई और इन दोनों बैंकों ने सट्टा बाजारों में सट्टा लगाया और अपने मुनाफे को बड़ी ही कुशलता से उद्योगों में निवेशित किया। इन दो बैंकों की सफलता के कारण 1850-57 के बीच कई साख की संस्थाएं खुली जिनमें क्रेडिट लियोने सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। गेरशेनक्रोन ने बताया है कि इन राज्य-प्रायोजित या राज्य-प्रोत्साहित बैंकों के कार्यकलापों ने रोथस्चाइलिइडस जैसे कई 'कंजरवेटिव' बैंकिंग घरानों को भी औद्योगिक बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आकर्षित किया जो अभी तक सरकारी ऋण-पत्रों और भूमि गहन तक ही सीमित थे। अतः इस युग में राज्य के सक्रिय सहयोग के कारण ही तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ। इस युग में मुक्त व्यापार की दिशा में कॉबडेंन संधि जैसे छिटपुट कार्य भी हुए जिसके द्वारा इंग्लैण्ड से सामान आयात होने वाले पर आयात शुल्कों में रियायत दी गई। सरकार के इस सक्रिय सहयोग की तुलना अठारहवीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार की सक्रियता से नहीं की जा सकती क्योंकि वे अधिक प्रभावकारी थे और इनकी दिशा भी सुनियोजित थी। हालांकि इन प्रयासों में प्रबंधकीय कमी थी परंतु यह महत्वपूर्ण थे और इसका प्रभाव अभूतपूर्व थे।

8.3 औद्योगिक पूँजीवाद का विकास 1871-1914

फ्रांस-प्रशा युद्ध (1870-1871) में फ्रांस की हार के बाद कई दशकों तक आमतौर पर यही समझा जाता रहा कि यह देश अवनति के गर्त में चला गया है। हालांकि जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका (जहाँ उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी और जहाँ जनसंख्या में तेज़ी से विकास हुआ था) से इसकी तुलना करने के कारण यह धारणा बनी थी। परवर्ती काल से तुलना करने पर पता लगता है कि 1871-1914 के मुकाबले 1815-1870 में उद्योग और कृषि की वृद्धि दर ज़्यादा थी। इस समय और इसके बाद फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों और औद्योगिक और वित्तीय पूँजीवाद के मज़बूत होने के महत्व को टीकाकारों ने कम करके आंका। कृषि और वानिकी में लगे श्रम बल का प्रतिशत 1870 में 53% था जो 1913 में घटकर 37.4% हो गया। श्रम की उत्पादकता बढ़ती रही और राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हुई (1895 तक यह धीरे-धीरे बढ़ीः 1896-1913 में यह वृद्धि प्रतिवर्ष 1.8% थी)। प्रति व्यक्ति निर्यात और आयात मूल्य में दोगुनी वृद्धि हुई। देश की बचत बढ़ी और देश के बाहर उद्यमों में पूँजी निवेश में भारी मात्रा में वृद्धि हुई। इस आर्थिक विकास में पश्चिम अफ्रीका और हिन्द चीन (दक्षिण पूर्व एशिया) में स्थापित फ्रांसीसी उपनिवेशों का योगदान भी शामिल था।

निम्नलिखित आँकड़ों से औद्योगिक वृद्धि के आम संकेतकों का उल्लेख किया जा रहा हैः

फ्रांस में विशिष्ट उद्योगों की उत्पादन वृद्धि की औसत वार्षिक दर (%)

अवधि	लोहा और इस्पात	कोयला	कपड़ा
1860-92	2.58	3.24	1.52
1892-1913	4.01	2.04	1.92

(**स्रोतः** एस.बी. सॉल और ए. मिलवार्ड, द डेवेलपमेंट ऑफ द इकोनोमिज़ ऑफ कान्टिनेंटल यूरोप (1977)

इसके अलावा यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस समय फ्रांस से रसायनों के उत्पादन और बिजली उद्योगों के क्षेत्र में पर्याप्त शोध और विकास हुए। इस समय जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा था। सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए नई खोज (सोडा बनाने की सॉल्वे पद्धति) मानक बन गई और सेंटडेरिस कंपनी ने रंग-सामग्री अनुसंधान और उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। बिजली के क्षेत्र में थॉमस-हयूसटन और सिमेंस जैसी अमेरिकन और जर्मन कंपनियों ने फ्रांस में उत्पादन शुरू किया जबकि फ्रांसीसी कंपनी ब्रेगे ने टेलीग्राफ और टेलीफोन उपकरणों के निर्माण शुरू किया। इसी समय अल्यूमुनियम के उत्पादन के लिए हेओ ने एलोक्ट्रोलाइसिस पद्धति की खोज की जो उस समय का महत्वपूर्ण नवाचार थी। मोटर कार उत्पादन के लिए बिजली के उत्पादों का उपयोग किया जाने लगा। फ्रांस की पेनहा और पूजों, कंपनियां जर्मनी की ओटो और बेंज कंपनियों से मुकाबला करने लगी और 1900 तक आते-आते ये कंपनियां फोर्ड से भी प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम रही।

1871 में अल्जास और लॉरेन पर जर्मनी का कब्ज़ा हो गया और यह फ्रांस के हाथ से निकल गया। आरंभ में ऐसा लगा कि फ्रांसीसी औद्योगिक पूँजीवाद के लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था जैसा बाद में साबित हुआ। निश्चित रूप से अल्जास में कपड़े के क्षेत्र में नवाचार अब जर्मनी के क्षेत्र में था। इसका फायदा मुख्य रूप से जर्मनी को ही मिल रहा था परंतु लॉरेन में फ्रांसीसी निर्माणकर्ताओं और अन्य फ्रांसीसी कंपनियों के बीच सम्पर्क इसके जर्मनी में मिलाने के बाद भी बने रहे। लौरेन के बड़े इस्पात और लौह उत्पादकों द वेन्डेल्स और श्नाईडर की लू क्रूजो कंपनी के बीच सहयोग बने रहने के कारण सीमा के दोनों ओर इस्पात बनाने के लिए थॉमस गिलक्राइस्ट पद्धति का इस्तेमाल किया जाने लगा जबकि 1878 से लेकर 1895 तक इस पद्धति पर द वेन्डलस के अधिकार सुरक्षित थे।

बोध प्रश्न 1

1) फ्रांस में 1848-70 के बीच औद्योगीकरण के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

2) 1871 में जर्मनी के हाथों अल्जास और लॉरेन के हार जाने का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा?

....

....

....

....

....

8.4 जर्मनी : परिवर्तन के स्रोत

1871 से पहले जर्मन राज्यों और उसके बाद जर्मन साम्राज्य ने उन्नीसवीं शताब्दी में काफी औद्योगिक पूँजी का विकास देखा। 1789-1815 के बीच उठाए गए सरकारी कदमों से भी इस क्षेत्र में पूँजीवाद की प्रकृति पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। फ्रांस के क्रांतिकारियों के प्रत्यक्ष प्रशासन वाली सरकारों या उसके आसपास की सरकारों जैसे राइनलैंड और बाद में वेस्टफेलिया साम्राज्य में फ्रांसीसी विधान का अनुगमन किया गया। नेपोलियन आक्रमण का सामना करने के उद्देश्य से सामाजिक संबंधों की प्रकृति में बदलावों के प्रयास शुरू हुए। महाद्वीपीय व्यवस्था और ब्रिटेन द्वारा महाद्वीप के बन्दरगाहों को अवरुद्ध किए जाने से (1806-1813) इस महाद्वीप में ब्रिटिश वस्तुएं नहीं पहुँची और इससे लगभग सभी क्षेत्रों को फायदा हुआ।

8.4.1 नेपोलियन युग के विधान

सबसे पहले राइनलैंड की औद्योगिक बस्तियों में श्रेणियों को तोड़ा गया और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया जिससे कई उद्योगों में प्रतिस्पर्द्धाओं के स्तर में सुधार हुआ और नवाचारों के लिए माहौल बना। महाद्वीपीय व्यवस्था से इस क्षेत्र के उत्पादों की माँग बढ़ी और फ्रांसीसी वसूलियों के बावजूद 1800 के दशक में ज्यूलिख, क्रेफेल्ड, आकेन, वूपर घाटी और डची ऑफ बर्ग में तीव्र आर्थिक उछाल आया। इस संदर्भ में ट्रेकबिलकॉक का कहना है कि 1800-1807 के बीच आकेन के कई ऊन के कारखानों में 5 गुना उत्पादन बढ़ा और रूस और स्पेन को बड़ी मात्रा में ऊन निर्यात की गयी।

प्रशा में पुरातन शासन पद्धति (Ancien Regime) को बचाने के लिए क्रांतिकारी व्यवस्थाओं को अपनाया गया जहाँ कृषि दासों को मुक्त करके जमींदार और किसान के बीच तथा किसान तथा राज्य के बीच नया संबंध विकसित हुआ। इनके तात्कालिक प्रभाव के बावजूद 1815 में सांम्राज्य की पुनर्स्थापना के बाद प्रशा में अन्य स्थानों पर राइनलैंड की संस्थागत पद्धति के साथ-साथ श्रेणियां भी जीवित रहीं। प्रशा में कृषि दासों की मुक्ति का प्रभाव सीमित होने के बावजूद निर्णायक और सर्वव्यापी था।

1807-8 मुक्ति आदेश (Emancipation Edicts, फॉन स्टीन नाम के मंत्री के प्रयत्न से) के द्वारा कृषि दासों को मुक्त तो कर दिया गया परंतु ज़मीन पर उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। हार्डनबर्ग नाम के एक मंत्री की देखरेख में 1811 में और भी कई उपाय किए गए जिनके अनुसार जिन कृषि दासों को जंकर सम्पत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार था उन्हें अपने खेतों का एक तिहाई हिस्सा ही छोड़ना होगा, जिनके पास इस तरह के अधिकार नहीं थे उन्हें अपनी आधी ज़मीन छोड़नी होगी, जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन होगी उन्हें केवल लगान देना होगा। नई व्यवस्था होने तक जिसमें कई वर्ष लगे कृषि दासों के सम्पत्तिगत

अधिकारों को निर्धारित करने के लिए पुरानी पद्धति को ही आधार बनाया गया। अन्ततः 1816 में ऐसे भाग्यशाली किसानों की सम्पत्ति के लिए उद्घोषणा हुई जो पशु भी पालते थे और बाकी को भाग्य के भरोसे खेतिहर मजदूर बनने के लिए छोड़ दिया। 1850 तक सम्पत्ति संबंधी व्यवस्थाओं को नियमित करने के लिए बहुत ज़ोर नहीं दिया गया।

जर्मनी में रैंटनबैंकएन (Rentenbanken) के बनाने के साथ-साथ कुछ वैधानिक उपाय भी किए गए। इससे भूमिपतियों को कृषि दास मुक्ति के लिए भुगतान की अदायगी की गई और किसानों को लंबे समय में इसे अदा करने की व्यवस्था की गई। 1816 के बाद अन्य क्षेत्रों के साथ कृषि में मंदी आने के कारण माँग में गिरावट आई और इस प्रकार कुछ भूमियों का हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में हुआ। मुक्ति आदेशों से अब भूमि बाजारों का विस्तार सम्भव हुआ क्योंकि इसमें बड़े काश्तकार और दूसरे लोगों (जो अभी तक कृषि दास थे और अभी तक ज़मीन नहीं खरीद सकते थे) को ज़मीन खरीदने का अधिकार मिला। इसके परिणामस्वरूप कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ जो पहले संभव नहीं था। मंदी समाप्त हो जाने के बाद कृषि के वाणिज्यीकरण से पूर्वी प्रदेशों में कृषि क्षेत्र में उन्नति हुई।

8.4.2 जोल्विरेन

1815 के बाद 1820 के दशक के आर्थिक विकास में 1834 में प्रशा में जोल्विरेन (सीमा शुल्क संघ) की स्थापना के पहले बड़े क्षेत्रीय बाज़ारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोल्विरेन ने जर्मन राज्यों में उत्पादित वस्तुओं के वितरण की कई समस्याओं और बाधाओं का समाधान हो सका। अभी तक इन्हीं बाधाओं के कारण इन क्षेत्रों में औद्योगिक पूँजीवाद का उदय नहीं हो सका था क्योंकि यहाँ के उत्पादक अपने माल या तो संरक्षित फ्रांसीसी बाज़ार में बेच सकते थे या उन्हें बाज़ार में अंग्रेजी माल की प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता था। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित क्षेत्रीय इकाइयां निर्मित की गईं।

क) प्रशा के बाज़ार में 1818 के सीमा-शुल्क के तहत कच्चे मालों पर कम सीमा-शुल्क लगाया गया। चाय और कॉफी जैसे 'औपनिवेशिक वस्तुओं' पर ज़्यादा सीमा-शुल्क लगाया गया (20%), उत्पादित वस्तुओं पर कम शुल्क लगाया गया (10%) और वस्तुओं के आने जाने पर ज़्यादा शुल्क लगाया गया।

ख) बवेरिया और वर्टेमबर्ग में साउथ जर्मन लीग की स्थापना की गई (1928)।

ग) सेंट्रल लीग बनाया गया (सेक्सोनी, हैनोवर, थरिजियन राज्य, कोबर्ग और हेंस)।

घ) प्रशा की भौगोलिक स्थिति काफी लाभप्रद थी (पोलैंड और रूस जाने वाले राज्य मार्ग इसके क्षेत्र से गुज़रते थे और फ्रैंकफर्ट तथा लिपजिग जैसे महत्वपूर्ण शहर इस मार्ग पर स्थित थे। निम्न राइन नदी के दोनों किनारे भी इसके नियंत्रण में थे)। अपनी इस भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर प्रशा ने 1834 के बाद से दूसरे राज्यों से सीमा शुल्क समझौता करने का आग्रह किया ताकि एक बड़ा बाज़ार बनाया जा सके। हेन्स के कस्बों, हैनोवर, होल्सटीन, मैकलेनबर्ग और ओल्डेनबर्ग को छोड़कर सभी राज्य 'जोल्विरेन' में शामिल हुए। सभी सदस्य राज्यों में प्रशा के 1818 के सीमा-शुल्क (कुछ छोटे मोटे संशोधनों के साथ) को लागू किया गया।

8.4.3 रेलवे

व्यापार समझौतों की इस व्यवस्था के अंतर्गत जर्मन राज्यों में रेलवे के विकास के कारण सिलेसिया और राइनलैंड में लोहा और कोयला उत्पादन में नवाचार अपनाये गए जिससे उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। रेलवे लाइनों के निर्माण के कारण घरेलू बाज़ार का विस्तार हुआ

जो राइन, एल्ब और ऑडर नदियों और उनसे जुड़ी नहरों से भलीभांति जुड़ा हुआ था। 1830 के दशक में रेलवे निर्माण शुरू हुआ। इस संदर्भ में प्रशा और सेक्सोनी में व्यापक विचार-विमर्श हुआ। फ्रेडरिक लिस्ट और फ्रेडरिक हारकोर्ट ऑफ वेटर अपने समर्थकों के साथ रेलवे निर्माण का समर्थन कर रहे थे और प्रशा के राजा के सलाहकार क्रिश्चन फान रोथर और उनके साथी इसका विरोध कर रहे थे। प्रशा में निजी क्षेत्र ने रेलवे लाइन बिछाने में मुख्य भूमिका निभाई। ये लाइनें 1838, 1840, 1841, 1843, 1848 में बिछाई गईं। जबकि बावेरिया और बैडेन में राज्य ने रेलवे का निर्माण किया। 1850 तक 3660 मील लंबी लाइन बिछ चुकी थी और इसके बाद भी यह कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा था।

इन परिस्थितियों में लोहा और कोयला उद्योगों में विदेशी सहायता से विकास हो रहा था। ऊपरी सिलेसिया में कोयले के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई जबकि राज्य के नियंत्रण वाले रूहर और सार के कोयला खदान भी महत्वपूर्ण थे। 1838-50 के बीच कच्चे लोहे का उत्पादन 266,000 टन से बढ़कर 545,000 टन तक हो गया।

8.4.4 संयुक्त पूँजी बैंकों का विकास

पेरिस के क्रेडिट मोबाइलियर और बेल्यिज़यम के सोसाइटी जनरेल की तर्ज़ पर जर्मन राज्यों में संयुक्त पूँजी बैंकों के विकास से यह विस्तार संभव हो सका। अभी तक उद्योग को मुनाफों के पुनर्निवेश, व्यापारिक पूँजी या उस क्षेत्र के 'कंजरवेटिव' बैंकिंग घरानों पर निर्भर करना पड़ रहा था जो सरकार या भूमिपतियों को ऋण देना ज़्यादा पसंद करते थे (शाफोजेन या रोथ्सचाइल्डस जैसे घराने), हालांकि बैंक ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की स्थापना के बाद पूँजी निवेश का एक नया प्रारूप स्थापित हुआ। कोलोन के बैंकर्स, ओपेनहाइम, मेविसेन और दाइकमेन के समर्थन से कार्लसरूह के एक बैंकर मोरिज फॉन हावेन ने इस बैंकिंग घराने की स्थापना की। रोथ्सचाइल्डस ने फैंकफर्ट सिनेट में इसका जमकर प्रतिरोध किया। प्रशा के नागरिक सेवा अधिकारियों ने इसे हतोत्साहित किया जो कोलोन में शाफोजेन बैंकविरेन का वर्चस्व देखना चाहते थे। हालांकि मूल पूँजी पेरियेर्स से प्राप्त हुई जिनके साथ एक समझौते द्वारा सिंडिकेट का निर्माण किया गया और इसके बाद बैंक ने नॉर्थ जर्मन लायड शिपिंग कम्पनी, ऑस्ट्रियाई रेलवे और राज्य ऋणों में व्यापक रूप से निवेश किया।

इसके बाद निम्नलिखित उद्यमों की स्थापना हुई :

क) डेविड हौसमैन के नेतृत्व में डिस्कोन्टो-जेसलसाफ्ट; और बाद में बिस्मार्क के बैंकर ब्लिकोडर जिसने 'प्रशियन कांसोर्टियम के ज़रिए प्रशा सरकार के लिए राज्य ऋण उगाहने में निर्णायक भूमिका अदा की।

ख) बर्लिन्स हैंडेल्स जेसलसाफ्ट, जिसने ब्लिकोडर और मेन्डेलशोन (बर्लिन) तथा मेविसेन और ओपेनहाइम (कोलोन) के नेतृत्व में राइनलैंड और बर्लिन के बैंकों को एकजुट किया। इसने रेलवे में व्यापक निवेश किया।

ग) ड्रेजनर बैंक, डोयेचे बैंक और डर्मस्टाड बैंक।

घ) मैगडबर्ग हैंडल्स जेसलसाफ्ट, जिसने स्थानीय बाज़ारों पर ध्यान केंद्रित किया।

ङ) एफ.डब्ल्यू काइफाइसन रूरल कोओपरेटिव बैंक (इनकी शुरुआत 1862 में हुई) और शुलस्जे लिटिएज कोओपरेटिव बैंक (इसमें शिल्पी और दुकानदार शामिल थे) की अलग तरीके से स्थापना हुई जो खासतौर से वुर्टेमबर्ग और दक्षिण जर्मनी में केंद्रित थे।

8.5 1871 के बाद विकास

1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना के बाद औद्योगिक उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई जिसने 1852 के उछाल को जारी रखा। जोल्विरेन ने बाज़ार को एक सूत्र में पिरोया और 1870 के बाद फ्रांस द्वारा हर्जाने दिये जाने से सार्वजनिक व्यय का स्तर ऊँचा रहा। इन दोनों कारकों के कारण उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। 1870-74 की अवधि, जो साम्राज्य के स्थापना वर्ष (ग्रुन्डेरयारे) माने जाते हैं, में कुल घरेलू उत्पाद में तीव्र दर से वृद्धि हुई। 1873 के वित्तीय संकट के साथ मंदी आई जो 1879 तक जारी रही। इस मंदी से पूरा यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभावित हुआ परंतु इस स्थापना के संकट (ग्रुंडरक्रिसे) से अन्ततः आर्थिक प्रसार बाधित नहीं हुआ। थॉमस-गिलक्राइस्ट इस्पात निर्माण प्रक्रिया के पेटेन्ट किए जाने से जर्मनी को अपने फॉस्फोरिक कच्चे लोहे के संसाधनों के व्यापक उपयोग का मौका मिला, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे उपकरणों की माँग बढ़ी और परिणामस्वरूप इस अवधि में तेजी से विकास हुआ जिसके आँकड़े नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

जर्मन उद्योग (1870-1913) में प्रतिवर्ष उत्पादन की औसत वृद्धि दर

औद्योगिक क्षेत्र	उत्पादन वृद्धि का %
धातु उत्पादन	5.7
लौहा उत्पादन	5.9
इस्पात उत्पादन	6.3
धातुकर्म	5.3
रसायन	6.2
कपड़ा	2.7
वस्त्र और चर्मकर्म	2.5
गैस, पानी और बिजली	9.7

स्रोतः एस.बी.सॉल और ए मिलवार्ड, द डेवेलपमेंट ऑफ द इकोनोमीज ऑफ कॉन्टीनेंटल यूरोप (1977 पृ. 26)

यह देखा गया कि इस समय संयुक्त पूँजी बैंकिंग ने औद्योगिक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्पादकों को प्रतिस्पर्द्धा से बचने को प्रोत्साहित किया तथा कार्टेल और सिंडिकेट स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। कहने का तात्पर्य यह कि इन संगठनों की स्थापना किसी क्षेत्र में उत्पादन के मूल्य निर्धारण और उत्पादन नीति के संबंध में एक राय बनाने के लिए की गई। इन दबावों और परिस्थितियों के फलस्वरूप चार प्रमुख इस्पात कम्पनियों के मूल्यों और उत्पादों को नियमित करने के लिए 1904 में जर्मन स्टीलवर्क्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसी प्रकार के अन्य कार्टेल भी इस समय मौजूद थे।

इस अवधि में जर्मन उद्योग की सफलता का श्रेय बड़े बैंकों के विकास को जाता है। बैंकों ने उद्योगों के विस्तार के लिए धनराशि जुटाने में मदद की। इस अवधि में प्रमुख कम्पनियों के निदेशक मंडल में बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होते थे और उनके माध्यम से बैंक नीति निर्माण में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता था। इस व्यवस्था से निस्संदेह प्रतिस्पर्द्धा को सकारात्मक रूप से कम किया जा सकता था और उत्पादन को सुनियोजित किया जा सकता था। इसके फलस्वरूप जर्मन उद्योग अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा के लिए खड़ा होने लगा।

इस व्यवस्था में एक खराबी थी जिसे बहुत शिद्दत से महसूस किया गया : समझौतों के दौरान मज़दूरों का ख्याल नहीं रखा जाता था जिससे मज़दूरों में निराशा की भावना पैदा हो रही थी। विद्वानों का मानना है कि इन औद्योगिक टकरावों से हिंसा बढ़ी और शताब्दी का अंत होते-होते देश में वर्ग संघर्ष काफी तेज़ हो गया। विल्हेम-II के शासन काल में शाही सरकार ने आर्थिक कार्यकलाप और प्रबंधन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर वित्तीय पूँजी और औद्योगिक पूँजी की शक्तियों को दबाने की कोशिश की। 1914 के पहले उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। सरकार ने हिबेर्निया उद्यम को खरीदने की असफल कोशिश की जिसे इस उद्योग ने सफलतापूर्वक परास्त कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत के समय भी संकेन्द्रण से जन्म लेने वाले वर्ग-संघर्ष के समाधान के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे।

बोध प्रश्न 2

1) जर्मन राज्य द्वारा उठाए गए कदमों ने पूँजीवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की?

....

....

....

....

....

2) जर्मनी में 1871 के पश्चात औद्योगीकरण की प्रगति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

....

....

....

....

....

8.6 रूसी औद्योगीकरण में राज्य की भूमिका

रूस में औद्योगिक पूँजीवाद की प्रगति 1890 के दशक में हुई। इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी की तुलना में रूस कई दशकों पीछे था। देर में औद्योगीकरण होने के कारण रूस ने नई औद्योगीकरण रणनीतियाँ शुरू नहीं की बल्कि उधार की तकनीकी अपनाने का लाभ मिला। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक रूस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने अपर्याप्त संसाधनों के बावजूद यूरोप की एक बड़ी शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। अपने पूरे इतिहास में और सोवियत युग में भी रूसी औद्योगीकरण का यह राजनैतिक चरित्र रहा। रूस के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, यूरोप की बाकी जगहों की तुलना में, राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया। जार पीटर द ग्रेट (1689-1725) ने प्रथम रूसी औद्योगीकरण की शुरुआत करने की कोशिश की परंतु वे बहुत कामयाब नहीं हुए और यह अल्पकाल्पिक प्रयास था। सेना और नौ सेना के लिए अस्त्र और जरूरी वस्तुएं बनाने वाले इन कारखानों में कृषिदासों को मज़दूर रखा गया और यूरोप से प्राप्त की गई या चुराई गई बेहतरीन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल तीव्रता से किया गया। 1890 के दशक तक भूमिधर आभिजात्य वर्ग औद्योगीकरण के बिलकुल खिलाफ थे। राज्य ने निवेश, उपभोग

और उत्पादन का ज़िम्मा उठाया जो काम पश्चिम में पूँजीपति कर रहे थे। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिक पूँजीवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने चार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया; ये थे : बजट (राजस्व और खर्च के बीच संतुलन); मुद्रा (विदेशों में इसके मूल्य में स्थिरता); व्यापार संतुलन (आयात बनाम निर्यात मूल्य) और भुगतान संतुलन (ऋण अदायगी)।

औद्योगीकरण के लिए आवश्यक अधिसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट संबंधी स्थायित्व जरूरी था। विदेशी पूँजी के आगमन के लिए एक अच्छी मुद्रा व्यवस्था की आवश्यकता थी। आयातित प्रौद्योगिकी का भुगतान अनाज के निर्यात से करने के लिए व्यापार संतुलन अपने पक्ष में होना चाहिए था। अन्तिम बात यह कि रूस की अन्तरराष्ट्रीय साख ऋण के ब्याज की समय से अदायगी से जुड़ी थी क्योंकि राज्य ने अधिकांश ऋण बाहर से ही लिया था। रूस के पास एक तेज़ी से बड़ती हुई जनसंख्या और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन थे परंतु यहाँ के किसानों के गरीब होने के कारण आंतरिक माँग बहुत सीमित थी। व्यक्तिगत माँग के कमज़ोर होने के कारण राज्य को ही प्रमुख खरीदार की भूमिका निभानी पड़ती थी। राज्य ने इसके लिए कई कदम उठाए, मसलन, भारी उद्योगों से राज्य ने एकमुश्त खरीददारी की, उन्हें मुनाफा और ऋण की गारंटी दी।

रूस में उद्योग की शुरुआत देर से हुई इसलिए यह पश्चिमी उद्योग से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता था। अतः राज्य ने आयात और निर्यात पर कर लगाकर उन्हें संरक्षण देने का कार्य किया। परंतु इसके लिए उन्हें एक ओर कृषि और उद्योग के हितों के बीच आपसी संतुलन बनाए रखना पड़ा और दूसरी ओर अपनी राजस्व जरूरतों पर भी नज़र रखनी पड़ी।

1850 और 1870 के दशकों के बीच रूस में सीमा-शुल्क की दर अपेक्षाकृत कम थी। कम सीमा-शुल्क की इस अवधि में आयात तेज़ी से बढ़ा। कृषि निर्यात के विस्तार होने पर भी 1860-1870 के दशक में रूसी व्यापार घाटे का सामना कर रहा था क्योंकि आयातित वस्तुओं का मूल्य निर्यातित वस्तुओं से अधिक था। सीमा-शुल्क की दर कम रखकर रूसी राज्य ने भारी उद्योग की अपेक्षा कपड़ा उद्योग जैसे हल्के उद्योगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जो लोकप्रिय माँग की पूर्ति करते थे, न कि भारी उद्योग को जिनकी माँग मुख्यतः उद्योग क्षेत्र से ही आती थी। 1877 से और 1881, 1884, 1885, 1887 में उभरते धातु निर्माण उद्योग और खनन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात शुल्क बढ़ाया गया।

8.7 गेरशेनक्रोन प्रारूप

रूसी औद्योगीकरण के बारे में एलेक्जेंडर गेरशेनक्रोन का वर्णन काफी प्रभावीशाली रहा है। जिन्होंने खासतौर पर रूसी औद्योगीकरण की प्रक्रिया और आमतौर पर 'आर्थिक पिछड़ेपन' की परिस्थिति में औद्योगीकरण के लिए एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप में इस धारणा को अस्वीकार कर दिया था कि प्रथम या 'अग्रणी' औद्योगिक देश के अनुरूप ही विकास की प्रक्रिया चलती है और अनुगमन करने वाले राष्ट्र या बाद में औद्योगीकृत होने वाले देशों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया अनिवार्यतः समान होती है क्योंकि औद्योगिक क्रांति की पूर्व शर्तें भिन्न-भिन्न होती हैं। इसकी बजाए उन्होंने पिछड़ेपन के स्तर के अनुरूप विभिन्न राष्ट्रों में इन प्रक्रियाओं के बीच सैद्धांतिक और संस्थागत अन्तर पर बल दिया। उनके विचार से इसी अन्तर से औद्योगिक उत्पादन में उछाल, औद्योगिक वृद्धि की गति और परिणामस्वरूप औद्योगिक संरचनाएं निर्धारित होती हैं।

औद्योगीकरण के शुरुआती दौर में किसी देश विशेष के सापेक्ष पिछड़ेपन के अनुसार औद्योगीकरण की प्रकृति और प्रगति का स्वरूप इस प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित तरीके से बदल जाता है:

क) औद्योगीकरण की शुरुआत में जितनी तेज़ी से उछाल आएगा उसमें उतनी ही मज़बूती आएगी और उत्पादन की वृद्धि दर अपेक्षाकृत ऊँची रहेगी। रूस में 1890 के दशक में निम्न आधार से औद्योगीकरण की शुरुआत हुई थी और उस दशक में पूरे विश्व में यहाँ की औद्योगिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही थी।

ख) जो देश अधिक पिछड़ा होगा वहाँ पर बड़े संयंत्रों और उद्यमों पर उतना ही ज़्यादा ज़ोर दिया जायेगा औद्योगिक प्रगति उतनी ही ज़्यादा होगी। वस्तुतः 1900 तक आते-आते रूस विश्व की एक सर्वाधिक 'संकेंद्रित' अर्थव्यवस्था हो गई थी क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा यहा उत्पादन और श्रम में बड़े उद्यमों का अंशदान ज़्यादा था।

ग) जो देश अधिक पिछड़ा होगा वहाँ उपभोक्ता वस्तुओं के बदले उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन पर बल देने से भी औद्योगीकरण पर फर्क पड़ता है। हालांकि रूस में क्रांति होने से पहले कपड़ा उद्योग; प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्र सबसे बड़ा उद्योग था परंतु राज्य ने 1880 के दशक से लेकर 1913 तक प्रमुख रूप से खनन और धातु निर्माण उद्योगों में पूँजी निवेशित की।

घ) देश के अधिक पिछड़ा होने की दशा में जनसंख्या के उपभोग स्तर पर दबाव भी ज़्यादा होता है। 1890 के दशक से राज्य निर्देशित औद्योगीकरण उच्च अप्रत्यक्ष करों, अनाज के निर्यात और स्वास्थ्य, आवास और विद्यालयों जैसे 'सामाजिक' निवेश की अपेक्षाकृत अवहेलना के साथ आगे बड़ा। करों और सामाजिक सुविधाओं के अभाव ने सबसे अधिक मज़दूरों और किसानों को प्रभावित किया और लगभग 1900 के बाद ही औद्योगिक वस्तुओं के उपभोग की उनकी क्षमता बढ़ सकी।

ङ) पिछड़े देशों में नए उद्योगों को पूँजी उपलब्ध कराने के लिए विशेष संस्थाओं के निर्माण की भी अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके अतिरिक्त अपेक्षाकृत कम संकेंद्रित, बेहतर सूचनायुक्त निर्देशन से भी फर्क पड़ता है। ग्रेरशेनक्रोन का मानना था कि देश जितना पिछड़ा होगा वहाँ उन कारकों का नियंत्रण और व्यापकता उतनी ही ज़्यादा होगी।

रूसी औद्योगीकरण को एक विकसित राज्य का साथ मिला जिसमें एक शक्तिशाली वित्त मंत्रालय था जिसने उस समय किसी भी औद्योगिक देश की अपेक्षा यहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया। इसका दबाव इतना मज़बूत था कि लोगों के काम करने की पद्धति और जीवन-शैली पर भी इसका प्रभाव पड़ा और किसानों तथा मज़दूरों की वैध माँगें भी इससे प्रभावित हुई।

च) कृषि औद्योगीकरण में सक्रिय भूमिका निभाने में कम सक्षम थी क्योंकि यह नए उद्योगों को श्रम की बढ़ती उत्पादकता पर आधारित बढ़ा हुआ घरेलू बाज़ार प्रदान नहीं कर पा रही थी।

इस संदर्भ में हाल में जो अनुसंधान हुए हैं उससे इस प्रारूप पर पुनर्विचार और संशोधित करने की ज़रूरत महसूस की जाने लगी है। पूर्व अवधारणा की अपेक्षा प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में वृद्धि अधिक बेहतर थी। इसके अलावा 1880 और 1890 के दशकों में कृषि श्रम की उत्पादकता भी औद्योगिक दर से लगभग 75% बढ़ी। 1905 के बाद स्टॉलिपिन सुधारों (जिसने निजी खेती को प्रोत्साहित किया) और लोगों के साइबेरिया जाकर बसने से लोगों की आय भी बढ़ी और बाज़ार भी विकसित हुआ, खेती उपभोग भी बढ़ा और उत्पादन पद्धतियों में भी विविधता आई। अतः 1900 के बाद उद्योग के साथ-साथ कृषि का भी अधिकाधिक पूरक रूप में विकास हुआ।

विभिन्न देशों और युगों में औद्योगीकरण के आधारभूत तत्वों के अभाव का विकल्प प्रस्तुत करना गेरशेनक्रोन प्रारूप की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। रूस में औद्योगीकरण के क्षेत्र में राज्य ने हस्तक्षेप किया और उन कारकों पूर्ति का प्रयास किया जिनका अभाव था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में निजी उद्यमियों और जर्मनी में निवेश बैंकों ने जो भूमिका अदा की वही भूमिका रूस में राज्य ने निभाई। गेरशेनक्रोन का मानना था कि रूस और यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के बीच बढ़ते अंतर से जन्मे तनाव के कारण राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया था।

रूस में राज्य ने इसे विभिन्न तरीकों से सम्पन्न किया। व्यक्तिगत उद्यमियों के छोटे आदेशों की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार लोहा और इस्पात जैसी औद्योगिक वस्तुओं का सबसे बड़ा एकल खरीददार बन गया। 1913 में भी राज्य के बैंकों की संख्या और संसाधन निजी बैंकों की अपेक्षा मजबूत थे। बैंक ऋण की कमी के कारण राज्य चुने हुए उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराता था। इसके अलावा विदेशी पूँजी और कौशल का आयात करके राज्य ने छोटे और अयोग्य उद्यमी वर्ग को सहायता प्रदान की।

पहले यह माना जाता था कि इतने तेज औद्योगिक विकास के बड़े और विशाल कार्य के लिए संसाधन जुटाने का काम निजी उद्यम नहीं संभाल सकता है और राज्य को निजी पूँजीपतियों के समर्थन में आगे आना ही पड़ता है। बाद के खोजों से यह पता चलता है कि राज्य की प्रमुखता ने निजी उद्यमियों को बाधित किया और संशोधनवादी इतिहास ने बताया है कि सरकार राज्य नियंत्रण के बाहर बढ़ते निजी व्यापार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।

गेरशेनक्रोन प्रारूप के अनुसार जब औद्योगिक उछाल अपने पूरे उत्कर्ष पर होता है तो राज्य की सक्रिय भूमिका समाप्त हो जाती है और गैर-राज्य उद्यमों और पूँजी का प्रसार होता है। 1900 के बाद हुई औद्योगिक वृद्धि पहले की अपेक्षा राज्य की माँगों और रेलवे के विस्तार पर कम आश्रित थी। निवेश में बैंकों का अंशदान और भूमिका बढ़ी, कुल तैयार माल के उत्पादन में हल्के उद्योगों का अंशदान बढ़ा, कई आधाभूत वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपभोग की दर बढ़ी और 1900 तक 1910 के बीच रूसी उद्योग और बैंकिंग में विदेशी पूँजी के अंतःप्रवाह की दर धीमी हुई।

8.8 औद्योगिक प्रवृत्तियां : 1860 के दशक से 1890 के दशक तक

1860 के दशक के उत्तरार्द्ध और 1870 के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक उत्पादन और बाज़ार में तेज़ी से वृद्धि हुई, संयुक्त पूँजी कम्पनियां स्थापित की गईं और रेलवे का जाल बिछाया गया। 1873 से पूरे यूरोप के संकट से रूस की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई और रूसी अर्थव्यवस्था में माल का उत्पादन खपत से ज़्यादा होने लगा, चीजों की कीमतें गिर गईं, कई उद्योग और बैंक बन्द हो गए। हालांकि मुख्य रूप से इस संकट ने लोहा, इस्पात और ईंधन को प्रभावित किया परंतु समकालीन पर्यवेक्षकों ने रेलवे निर्माण में भी आई कमी को इसके लिए उत्तरदायी माना और उपभोक्ता उद्योगों में निवेश को भी इसने जल्द ही प्रभावित किया। 1870 के दशक के पूर्वार्द्ध में खराब फसल होने और अकाल पड़ने के कारण किसानों की क्रय शक्ति कमज़ोर हुई और इसके कारण बाज़ार संकुचित हुआ। 1877 में रूसी-तुर्की युद्ध के कारण सेना की माँग बड़ी और इससे उद्योग को बल मिला। इसके साथ-साथ 1878 और 1879 में अच्छी फसल होने से अनाज का रिकॉर्ड निर्यात हुआ।

परंतु यह स्थिति बहुत दिनों तक कायम नहीं रही। 1882 से लेकर 1885 तक औद्योगिक विकास में गिरावट आई। 1890 में भी अधिकांश क्षेत्रों में मंदी आई और 1891 में प्रलयकारी फसल नष्ट होने और परिणामस्वरूप अकाल पड़ने के कारण इसका प्रभाव तीखा हो गया। फसल न होने के साथ-साथ नए रेलवे में निवेश में कमी आई। इस संकट के दौरान 1880 के बाद पश्चिमी यूरोप, जो स्वयं संकटग्रस्त था, से ऋण मिलना भी कम हो गया। इससे संकट की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई, इस दौरान नई पूँजी और रेलवे लाइनों का निर्माण धीमी गति से हुआ, कारखाने बंद हुए और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैली।

1862 और 1882 के बीच औद्योगिक उत्पादन दोगुना हो गया। इस दौरान 3.5% की औसत दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। 1860 और 1890 के बीच कोयले का उत्पादन 2005% उछल गया, लोहा, इस्पात और पेट्रोलियम का उत्पादन चारगुना हो गया तथा रेलवे विस्तार में 2000% की वृद्धि हुई। 1860 और 1890 के बीच औद्योगिक श्रम बल दोगुना हो गया।

1880 के दशक के उत्तरार्द्ध और 1890 के दशक के पूर्वार्द्ध में रूस की आर्थिक परिस्थितियाँ पुनर्जीवित होने के लिए तैयार थी। धातु निर्माण, कोयला खनन और तेल उत्पादन में हुए विकास, कपास उत्पादन का मशीनीकरण और रेलवे निर्माण का पुनः आरंभ एक तरह से 1890 के दशक में होने वाले औद्योगिक विकास की एक पूर्व पीठिका ही थी।

यह उछाल मुख्य रूप से दो बातों पर आधारित थाः औद्योगीकरण के प्रति सरकारी नीति और यूरोप में शांति। 1860 के दशक में रूसी सरकार सर्वहारा वर्ग जैसे नए सामाजिक वर्गों के उदय से औद्योगिक विकास के संबंध में सशंकित हो गई और उसे उस बात की आशंका हो गई कि मज़दूरों में असंतोष फैलने से कृषिय समाज के ताने-बाने में खतरनाक तनाव आ जाएगा जिससे कुलीनवर्ग के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी।

1861 में कुलीनवर्ग को कृषिदास छिन जाने के एवज में जो भुगतान करना पड़ा था उसका आर्थिक प्रभाव 1860 के पूरे दशक में बना रहा। 1850 के दशक से लेकर 1870 के दशक तक क्रिमिया युद्ध और रूसी-तुर्की युद्ध के कारण राज्य सरकार का अधिकांश राजस्व उत्पादन में निवेश के बजाए सैन्य खर्चों की ओर चला गया जिससे विदेशों में रूसी रूबल की कीमत कम हुई और रूस में मुद्रा स्फिति आ गई।

1890 के दशक में जो औद्योगिक उछाल आया उसके लिए अन्तरराष्ट्रीय शांति जरूरी थी ताकि पूँजी, वस्तुओं और तकनीकी विशेषज्ञताओं का आदान-प्रदान हो सके जिन पर औद्योगिक उछाल निर्भर था। 1878 के बाद यूरोप में आई शांति का निकोलाई क्रिसटियानोविच बंज (1881-1887) और इवान अल्केसीविच विशेनग्रेडस्की (1887-1892) जैसे रूस के वित्त मंत्रियों ने सफलतापूर्वक उपयोग किया और रूस में बजट आधारित विस्तार, मौद्रिक स्थिरता और विदेशी निवेश की नींव रखी।

1890 के दशक से औद्योगीकरण रूसी राज्य का मुख्य और स्वीकृत उद्देश्य हो गया। 1893 के बाद वित्त मंत्री बने सरगेइ यूलेविच विट ने इस महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व किया। विट के उद्देश्य काफी हद तक राजनैतिक थे। चूंकि 1890 के दशक में दुनिया की बड़ी शक्तियों की तुलना में रूस पिछड़ा हुआ देश था इसलिए विट को प्रतिकूल परिस्थितियों में औद्योगीकरण करना था, तेज़ी से आर्थिक ताकत प्राप्त करनी थी क्योंकि औद्योगिक उत्पादकता के आधार पर ही राजनैतिक शक्ति तय होती थी।

बोध प्रश्न 3

1) गेरशेनक्रोन प्रारूप में 'विकल्पों' से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

....

....

2) 1890 के दशक में औद्योगिक उछाल की पृष्ठभूमि क्या थी?

....

....

....

....

....

....

8.9 विट व्यवस्था

रूस के वित्त मंत्री और रूसी साम्राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री– काँउट सरजेइ यूलेविच विट के अनुसार औद्योगिक मज़बूती की जड़ें रेलवे और भारी उद्योगों में निहित थी। विट व्यवस्था में सीमा-शुल्क संरक्षण, मौद्रिक स्थिरता, वित्तीय सुधार, भारी कराधान और विदेशी निवेश के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। उनका उद्देश्य निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करना और राजकीय पूँजीवाद के व्यापक कार्यक्रम के ज़रिए रूस के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना था। उन्होंने आशा जताई कि धातु निर्माण और ईंधन उद्योगों के विकास को बढ़ती शहरी और औद्योगिक माँग से बल मिलेगा। बढ़ती शहरी और औद्योगिक माँगों के कारण कृषि बाज़ारों का तीव्र गति से विकास होगा।

विट के अनुसार औद्योगीकरण में हुई देरी की पूर्ति और तेज दर से वृद्धि करने के लिए इंग्लैंड के बजाए जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी का आयात करना होगा और विशाल कारखानों की स्थापना करनी होगी जिसमें ढेर सारे मज़दूर एक साथ काम कर सकें। घरेलू पूँजी, उद्यमशीलता और कुशल श्रमिकों की कमी के साथ-साथ रूस और उसके राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच बढ़ती खाई के कारण इस प्रकार की विशेषताएं सामने आई।

यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि हालांकि राज्य के व्यापक हस्तक्षेप संबंधी विट व्यवस्था एक निर्भीक और समयानुकूल प्रयास था परंतु यह पूर्णतः नवीन विचार नहीं था। 1860 से ही पूर्व वित्त मंत्रियों, जैसे मिखाइल क्रिसटियानोविच, रयूटर्न (1862-78), एन. के. बंज और आई. ए. विशेनग्रेडस्की ने इस प्रकार की बातें सामने रखी थी। उन्होंने बजट संतुलन ठीक करने, रूबल को स्थायित्व प्रदान करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के कार्य पहले भी किए थे।

8.9.1 तीव्र वृद्धि

1890 के दशक में हुए औद्योगिक विकास में रेलवे निर्माण सर्वप्रमुख रहा। इस दौरान रेलवे लाइनों की लंबाई लगभग दोगुनी हो गई और इस प्रकार कुल रेलवे जालतंत्र की 37 % रेलवे लाइनें बिछीं या पिछले पचास सालों में जितनी लाइनें बनी थीं उनके 50 प्रतिशत के बराबर लाइनों का निर्माण 1890 के दशक में हुआ। 1890 और 1900 के बीच रेलवे के इंजन, सवारी और माल के डिब्बों आदि की संख्या भी दोगुनी हो गई। 1890-1905 के बीच रेलवे की संयुक्त पूँजी में वार्षिक वृद्धि औद्योगिक संयुक्त पूँजी में वार्षिक वृद्धि से अधिक थी और रेल तथा रेल के इंजन, डिब्बों आदि में निवेश करने से यूक्रेन स्थित नए लोहा इस्पात उद्योग तथ सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित इंजीनियरिंग उद्योग को विशेष रूप से समर्थन मिला। 1890 के दशक में रूस में लोहे के उत्पादन का एक तिहाई उत्पाद रेलवे में खप जाता था और इससे कोयले को भी बड़ा बाज़ार मिला। 1890 में रेलवे नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से रूस विश्व का पाँचवां देश था और 1900 में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका उससे आगे था। यह सही है कि रूस के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए यह विस्तार बहुत कम और अपर्याप्त था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महसूस किया गया। इसके बावजूद निस्संदेह रूप से रेलवे एक प्रमुख उद्योग था।

लगभग 1895 से रेलवे में निजी और राजकीय पूँजी का निवेश लगभग बराबर था परंतु सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी काफी अधिक थी क्योंकि राज्य द्वारा रेलवे निर्माण के लिए प्रत्यक्ष ऋण दिए जाने के अलावा सरकार सभी ऋणों पर मुनाफे की गारंटी देती थी और निजी कम्पनियों से महत्वपूर्ण या ऋण के बोझ से दबे रेलवे को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। 1900 तक रूसी रेलवे की कुल पूँजी 4.7 बिलियन रूबल हो गई। इसमें लगभग 3.6 बिलियन सरकारी पूँजी थी जो कुल सरकारी ऋण के आधे से अधिक थी। 1890 के दशक में रूसी रेलवे में विदेशी निवेश 341 मिलियन रूबल था जो अन्य खनन उद्योगों या बैंकों की तुलना में काफी कम था।

उन्नीसवीं शताब्दी में और 1890 के दशक तक कपड़ा उद्योग सभी उद्योगों से काफी आगे रहा। हालांकि विट ने खासतौर पर सूती वस्त्र उद्योग को समर्थन नहीं दिया था परंतु 1890 के दशक में इसके उत्पाद में प्रतिवर्ष 8% की दर से तीव्र वृद्धि हुई। 1899 तक यह उद्योग सबसे बड़ा नियोक्ता था और 7 औद्योगिक मज़दूरों में से 1 मज़दूर कपड़ा उद्योग में काम करता था। 1890 के दशक में सूती वस्त्र उद्योग का मशीनीकरण कर दिया गया।

इस उच्च स्तरीय प्रभावशाली विकास (यह विकास उस समय पूरे विश्व में तीव्रतम था) का आधार भारी उद्योग था। रूसी राज्य भी भारी उद्योग का ही विकास करना चाहता था। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष वृद्धि दर का प्रतिशत इस प्रकार था :

खनन, 11.2; रसायन, 10.7; इमारती लकड़ी, 9.3; धातु निर्माण, 8.4; चीनीमिट्टी (सेरामिक्स) 8.0; कपड़ा उद्योग, 7.8 और खाद्य प्रसंस्करण 1.7। इस समय उत्पादकता में भी तीव्र वृद्धि हुई। एक ओर वस्त्र उद्योग में जहाँ उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ मज़दूरों की संख्या में भी वृद्धि हुई वहीं खनन और धातु उत्पादन में 1887-97 के बीच उत्पादन 152% बढ़ा जबकि श्रम-बल में केवल 39% की वृद्धि हुई। 1890 के दशक में हुए औद्योगिक उछाल का एक प्रमाण यह है कि 1900 में मौजूद सभी औद्योगिक उद्यमों में से 40% औद्योगिक प्रतिस्थानों की स्थापना 1891 के बाद ही हुई।

8.9.2 राजस्व और कराधान

विट ने अपनी औद्योगिक नीतियों को बल प्रदान करने के लिए अधिक राजस्व जुटाने और रूबल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य को स्थायित्व प्रदान करने की जरूरत थी। 1890 का दशक विदेशों से ऋण लेने के लिए सर्वथा उपयुक्त था क्योंकि ब्याज की दरें कम थी; इसलिए उन्होंने महंगे घरेलू ऋणों के स्थान पर सस्ते विदेशी ऋण लेकर एक बिलियन रूबल की बचत की। विट ने 1880 के दशक में हासिल किए गए व्यापार संतुलन को बरकरार रखने के लिए संरक्षणवादी सीमा-शुल्क नीति अपनाई और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया। इसके लिए रूसी उद्योग को राज्य ने करों में छूट और मुनाफे की गांरटी के रूप में प्रत्यक्ष समर्थन दिया। 1891 के सीमा-शुल्क अधिनियम में, जो उस समय विश्व की तुलना में रूस में सबसे भारी सीमा-शुल्क था, केवल चौदह उत्पादों को ही मुक्त रखा गया; यह भी वह उत्पाद थे जिनकी रूस में काफी कम माँग थी। कच्चे माल और उत्पादित वस्तुओं पर ऊँचा आयात शुल्क लगाया गया। इन उच्च शुल्कों के कारण धातु निर्माण उद्योग की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई और इस प्रकार रूस में मशीन निर्माण उद्योग के उदय को प्रोत्साहन मिला।

परंतु विट के सामने अभी भी दो समस्याएं थीं। रेलवे में राज्य का निवेश काफी हो जाने के कारण उसे अपने बजट को संतुलित करने के लिए आमदनी की भी जरूरत थी। दूसरी ओर रूस की प्रमुख निर्यात-वस्तु अनाज का मूल्य काफी गिर गया जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होने लगी। रूस के घरेलू बजट को संतुलित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विट ने कर की दर ऊँची कर दी। उसने अप्रत्यक्ष कराधान का सहारा लिया; 1890 के दशक में कुल राजस्व का लगभग आधा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता था। इस ऊँचे कराधान का बोझ सबसे ज़्यादा गरीब किसानों को उठाना पड़ा; इसीलिए यह कहा भी जाता है कि रूसी औद्योगीकरण की कीमत किसानों को चुकानी पड़ी।

राज्य समर्थित विकास के लिए धन जुटाने हेतु करों और ऋणों की नीति अपनाई गई और दूसरी ओर मुद्रा में स्थायित्व लाने और स्वर्ण को मानक के रूप में अपनाया गया। विट रूस में विदेशी पूँजी के आगमन को तेज़ करना चाहता था। मुद्रा अवमूल्यन से प्रभावित देश को विदेश से ऋण मिलने में कठिनाई होती थी। इसके लिए राज्य द्वारा विदेशी ऋणदाताओं को उनकी पूँजी पर मुनाफे और ऋण पर ब्याज देने की गारंटी देने की ज़रूरत थी। इसके लिए रूबल को स्वर्ण भंडार का समर्थन भी चाहिए था; इसलिए स्वर्ण मानक को अपनाना रूस के लिए अनिवार्य हो गया।

यह 1877 के बाद संभव हुआ जब आयात शुल्क की वसूली कागज़ के रूबल में न करके सोने के रूबल रूप में की जाने लगी। दूसरे, विनिमय नियंत्रण और राज्य के बैंक द्वारा नोट जारी करने से ज़्यादा स्वर्ण भंडार रखने की नीति से रूबल खुद स्थिर हो गया। इसके अलावा, भारी कराधान की नीतियों के फलस्वरूप पर्याप्त स्वर्ण भंडार जमा हो गया और अन्ततः 1896 में फसल अच्छी हो जाने से जनवरी 1897 में रूबल को स्वर्ण मानक पर आधारित कर दिया गया।

इससे कई लाभ हुए। रूबल की विनिमय दर में स्थिरता आई, विदेशों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा हुई और 1897 और 1913 के बीच हुए विदेशी निवेश का स्तर 1881 और 1897 के बीच हुए निवेश से दोगुना था। परंतु इसके लिए जनता पर करों का अतिरिक्त बोझ लादना पड़ा, बलपूर्वक अतिरिक्त का निर्यात करना पड़ा और रूस के स्वर्ण भण्डार को अचल बना दिया गया।

8.9.3 विदेशी पूँजी की भूमिका

घरेलू स्रोतों की अपर्याप्तता के कारण विदेशी पूँजी की आपूर्ति अपरिहार्य थी। रूस में विदेशी पूँजी के अंर्तप्रवाह को प्रोत्साहन देने से 1914 तक रूस यूरोप का सबसे बड़ा कर्ज़दार देश बन गया। रूस के राष्ट्रीय ऋण में 1895 में विदेशियों का हिस्सा 30% था जो 1914 में बढ़कर 48% हो गया। राज्य ने संभवतः आधे से ज़्यादा विदेशी निवेश रेलवे ऋणों के रूप में था। बाकी निवेश उद्योगों, खासकर दक्षिण में खनन और धातु कर्म उद्योगों और काकेशस के तेल उद्योग के साथ-साथ बैंक और व्यापार क्षेत्र में हुआ। 1890 के बाद में फ्रांस और बेलजियम ने रूस में सबसे ज़्यादा निवेश किया। रूसी औद्योगीकरण में विदेशी उद्यमशीलता का अध्ययन करने वाले लेखक जे. पी. मैके के आकलन के अनुसार 1890 में रूस में संचयी विदेशी पूँजी 215 मिलियन रूबल थी जो 1900 में 911, 1910 में 1,358 और 1915 में बढ़कर 2,206 मिलियन रूबल हो गई। नए औद्योगिक निवेशों में इसका योगदान 1890-92 में 33% था जो 1900-02 में बढ़कर 47% और 1909-13 में 50% हो गया। रूस में इस अवधि में इतनी भारी मात्रा में विदेशी पूँजी का प्रवेश क्यों हुआ? 1850 के बाद यूरोप के बुर्जुआ वर्ग के पास विदेशों में ऋण देने के लिए काफी मात्रा में अधिशेष राशि थी। अन्य देशों की अपेक्षा रूस इस पूँजी को अपनी ओर आकर्षित करने में क्यों सफल रहा?

पश्चिमी यूरोप की तुलना में रूस में मुनाफे की दर अधिक थी। सरकार ने सीमा-शुल्क संरक्षण प्रदान किया था, ऋण और मुनाफे पर गारंटी दी थी तथा मज़दूरों द्वारा औद्योगिक कार्यवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। स्वर्ण मानक अपनाने से रूस की साख बढ़ गई थी। इसके अलावा 1890 के दशक में विश्व में ब्याज की दर कम होने के कारण रूस में निवेश करना आकर्षक सिद्ध हुआ।

इसमें राजनैतिक कारकों का भी योगदान रहा। उदाहरण के लिए, रूस से मित्रता करने के लिए जर्मन और फ्रांसीसी सरकारों ने रूस में निवेश को प्रोत्साहित किया। 1879 जर्मनी के साथ संधि के फलस्वरूप, जिसे *ड्रिकाइजरबंड़* के नाम से जाना जाता है, 1870 के दशक के उत्तरार्द्ध और 1880 के पूर्वार्द्ध में रूस में जर्मन पूँजी का आगमन तेज़ी से हुआ। 1894 में फ्रांस के साथ संधि हुई। इसी प्रकार 1907 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ जिसके कारण रूस में ब्रिटिश पूँजी का तेज़ी से आगमन हुआ।

8.9.4 1890 के दशक में तेज औद्योगिक विकास का मूल्यांकन

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में रूस निस्संदेह एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति में रूपांतरित हो गया था। रूस में कुल विश्व उत्पादन का 6% लोहा और इस्पात का उत्पादन होने लगा जिससे औद्योगिक शक्तियों में इसका स्थान चौथा हो गया; पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका (42%), जर्मनी (18%) और ग्रेट ब्रिटेन (14%) थे। इसके अलावा रूस में आधुनिक इंजीनियरिंग उद्योग का निर्माण हो रहा था। इसके साथ-साथ आधारभूत रसायनों जैसे उद्योग भी उभर रहे थे। शहरी जनसंख्या बढ़ने से उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की भी उन्नति हुई। बड़े पैमाने पर रेलवे के निर्माण के कारण आर्थिक प्रगति हुई, परिवहन की लागत घटी, अन्तरक्षेत्रीय व्यापार बढ़ा और साइबेरिया तथा मध्य एशिया जैसे आर्थिक अवसरों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का आवागमन बढ़ा।

हालांकि ये सारी प्रभावशाली उपलब्धियां उद्योग में राज्य के निवेश, किसानों पर करारोपण और पश्चिमी यूरोप से लगातार आनेवाले ऋणों और पूँजी निवेशों की नाजुक नींव पर आधारित थी। विट व्यवस्था में, राज्य नीतियों ने कृषि पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान निवेश उद्योग पर केंद्रित किया। विट का यह मानना था कि उद्योग की

उन्नति होने से इसका कुछ भाग अपने आप 'रिसकर' कृषि तक पहुँच जाएगा और कृषि की उत्पादकता और उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए कृषि क्षेत्र के लिए अलग से नीति बनाने की ज़रूरत को नजरअंदाज कर दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र में भी उपभोक्ता उद्योगों की अपेक्षा भारी उद्योगों में अधिक निवेश किया गया और उन्हें ज़्यादा संरक्षण दिया गया। ये सब विट व्यवस्था की गंभीर खामियां थीं। कृषि के हितों की रक्षा करने के पक्षधर अधिकारियों और कुलीनवर्गों का विरोध बढ़ता गया। एक स्वायत्त रूसी पूँजीवादी समर्थन के अभाव में इस अभियान में कमजोरी थी।

8.10 1901 से 1914 तक औद्योगिक पूँजीवाद

1890 के दशक का यह उछाल 1901 की मंदी के बाद समाप्त हो गया। सबसे आधारभूत समस्या यह थी कि 1890 के दशक में किसानों का जीवन स्तर गिर गया था और उनकी कर अदा करने की शक्ति क्षीण हो गई थी। 1897 और 1901 बीच लगातार औसत अनाज का उत्पादन कम हुआ जिससे अनाज उत्पादक इलाके प्रभावित हुए। इससे मुक्ति भुगतान और दूसरे प्रकार भुगतानों का बकाया बढ़ता गया और निर्यात से होने वाली आय में कमी आई। इसका मतलब यह हुआ कि उद्योग में सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय को अब 1890 की दशक के स्तर पर बनाए नहीं रखा जा सकता था जबकि व्यापार और भुगतान संतुलन बुरी तरह प्रभावित हुए थे।

8.10.1 संकट

1899 के मध्य से मुद्रा बाज़ार की स्थिति विकट हो गई; यही औद्योगिक संकट का तात्कालिक कारण बना। पूरे विश्व में ब्याज की दर बढ़ने और अन्तरराष्ट्रीय निवेश का प्रवाह धीमा होने के प्रतिकूल प्रभाव केवल रूस पर ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूरोप पर भी पड़े। इस औद्योगिक संकट के कारण कई उद्योग दिवालिया हो गए, औद्योगिक मूल्यों में तेज़ी से कमी आई, खासकर बड़े उद्योगों में उत्पादन संकुचित हुआ और ढलवा लौह, लोहे और कच्चे तेल का अत्यधिक उत्पादन हो गया। 1902 का वर्ष जो सबसे खस्ता हाल वर्ष था, उसमें लगभग 2400 औद्योगिक इकाइयां बन्द हो गईं जिनमें से एक तिहाई इकाइयां क्रिवोई रोग के खनन क्षेत्र में थीं और बड़े धातु उत्पादक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का एक चौथाई हिस्सा बंद हो गया। औद्योगिक बेरोज़गारी अब 90,000 तक पहुँच गयी। ब्याज दरें बढ़ गई और षेयरों के मूल्यों में गिरावट आई। अपनी पूँजी भंडार को बचाए रखने के लिए बैंकों ने ऋण पर प्रतिबंध लगा दिया और उद्योगों के लिए कार्यशील पूँजी प्राप्त करना भी कठिन हो गया। 1890 के दशक में भारी उद्योग की जिन शाखाओं में तेज़ी से विकास हुआ था वही इस मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुईं।

इस संकट के कारण 1903 में वित्त मंत्री विट को मंत्रालय से निकाल दिया गया। सरकार की औद्योगिक नीतियों के विरोधियों ने इस औद्योगिक संकट को प्रमाण के रूप में पेश करते हुए कहा कि किसान की उपभोक्ता वस्तुओं पर भारी कर लगाने का विचार गलत था और रूसी औद्योगीकरण कृत्रिम था क्योंकि यह मुख्य रूप से सरकारी आदेशों और माँगों पर आधारित था।

8.10.2 एकाधिकार स्थापित करने के तरीके

रूसी उद्योग में संकट आने से उत्पादन और विक्रय को नियंत्रित करने के लिए कई एकाधिकार मूलक उपाय इस्तेमाल किए गए। प्रत्येक क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिए बड़ी कम्पनियों के 'सिंडिकेट' बनाए गए। जिन उद्योगों में विदेशी पूँजी निवेशित थी उनमें यह

प्रवृत्ति 1902 के बाद तेज़ी से विकसित हुई। धातु निर्माण उद्योग में प्रोडामेट (1902); रेलवे वाहनों के लिए प्रोडवैगन (1906), डोनेट कोयले के लिए प्रोडुगोल (1906) इस प्रकार के संगठनों के कुछ उदाहरण हैं। 1914 तक इस प्रकार के 150 से भी ज़्यादा संगठन स्थापित हो गए थे और वे न केवल खनन और धातु निर्माण क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे बल्कि वस्त्र और चीनी जैसे हल्के उद्योगों की कुछ शाखाओं को भी नियंत्रित करते थे।

जर्मनी में भी इसी प्रकार के संगठन स्थापित थे जिन्हें 'कार्टेल' के नाम से जाना जाता था। परंतु रूस के इन संगठनों और जर्मनी के इस कार्टेल में कई तरह की असमानताएं थीं। रूस के ये संगठन एक ढीले-ढाले संगठन थे जिनका मूल उद्देश्य मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित करना और उद्योग विशेष में प्रतियोगिता पर काबू रखना था। उनकी विधियां अलग-अलग थीं। कुछ ने परिवहन और विक्रय लागत बचाने के लिए आदेश आवंटन को अपने हाथ में ले लिया था और कुछ ने साख की षर्तों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये सिंडिकेट आमतौर पर बिक्री एजेंसियां होती थीं जो उत्पादन को नियमित करने के लिए न के बराबर हस्तक्षेप करती थीं।

1901 से लेकर 1914 तक औद्योगीकरण की प्रतिवर्ष वृद्धि दर 6% रही। 1901-1903 के संकट ने राज्य के आदेशों और रेलवे निर्माण पर आधारित औद्योगिक नीतियों की कमज़ोरियों का पर्दाफाश कर दिया क्योंकि इससे उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग कम प्रभावित हुए। इसी प्रकार युद्ध पूर्व वर्षों से लेकर 1914 तक औद्योगिक पूँजीवाद धीमी गति से और सचेत होकर एक परिवर्तित ढ़ाँचे में आगे बढ़ा। 1904-1905 में जापान के साथ युद्ध और 1905-1907 की प्रथम रूसी क्रांति के साथ-साथ मुक्ति भुगतानों के उन्मूलन और करों के भुगतान की संयुक्त ज़िम्मेदारी के सिद्धांत के कारण बजट पर दबाव और भी बढ़ा। रेलवे निर्माण कम हुआ और इसकी गतिविधि धीमी रही।

गेरशेनक्रोन के प्रारूप में राज्य के स्थान पर बैंक उद्योग को वित्त प्रदान करने की प्रमुख भूमिका निभा रहे थे और इसके लिए विदेशी निवेश भी जुटा रहा था परंतु इसे प्रमुखतः रूसी कम्पनियों के ज़रिए निवेशित किया जा रहा था।

1907-8 में मंदी का नया दौर आया जिसने कई औद्योगिक क्षेत्रों को प्रभावित किया। कोयला, लोहा और इस्पात, सूती वस्तुओं और परिशोधित तेल के उत्पादन में कमी आने के साथ-साथ मूल्यों में कमी आई और बेरोज़गारी में वृद्धि हुई।

8.10.3 1908-13 में हुआ विकास

सभी स्रोत इस बात से सहमत हैं कि 1908-13 के दौरान युद्ध होने के पहले के पाँच वर्षों में उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में नियमित और प्रभावी वृद्धि हुई। 1908 के बाद रूसी उद्योगों में पुनः तीव्र गति से प्रसार हुआ और इसको 1900 के पहले के मुकाबले कारखानों की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि से मदद मिली। 1908 और 1913 के बीच ढलवाँ लौह का उत्पादन 61%, कोयले का 73% और लोहे और इस्पात का उत्पादन 60% बढ़ गया। इसके चलते 1908-13 के बीच बड़े उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई; जो मौजूदा मूल्यों की दर पर प्रतिवर्ष औसतन 9% और 1913 के मूल्यों पर 7% थी। यह वृद्धि दर काफी अच्छी थी जो 1890 के दशक में हुई तीव्र वृद्धि के लगभग थी और 1900 और 1907 के बीच अर्जित सामान्य दर (वार्षिक दर मुश्किल से 1.5% से अधिक हो पाई थी) से काफी ज़्यादा थी।

1895 और 1905 के बीच की तुलना में 1905 और 1913 के बीच कृषि उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई। उपज में यह वृद्धि कृषि क्षेत्र के विस्तार और अधिक उपज देने वाले अनाजों के कारण हुआ, हालांकि अभी भी रूस में उपज कम ही थी। घरेलू और विश्व बाज़ारों में अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का मूल्य औद्योगिक वस्तुओं के मुकाबले में बढ़े। अनाज के निर्यात में वृद्धि होने से भी किसान घरेलू उद्योग के लिए बड़ा बाज़ार प्रस्तुत कर सके।

प्रथम विश्वयुद्ध के पहले उत्पादन, निवेश, मूल्य और मुनाफे में चारों ओर तीव्र गति से वृद्धि हुई। भारी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होने से भी सभी क्षेत्र प्रभावित हुए परंतु उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी समान गति से हुआ। रबर, जूता-चप्पल, ऊनी वस्त्रों, चर्बी और कुछ खाद्यान्न वस्तुओं में विशेष वृद्धि हुई। वस्तुतः 1913 तक खनन और धातु निर्माण जैसे आधारभूत उद्योगों का नहीं बल्कि उपभोक्ता वस्तुओं का औद्योगिक विकास में वर्चस्व रहा। यहाँ तक कि औद्योगीकरण के तीन दशकों बाद 1913 तक कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग आधा हिस्सा वस्त्र उद्योग और खाद्य वस्तुओं का था। खनन, धातु निर्माण और इंजीनिरिंग को मिलाकर होने वाले उत्पादन से यह दोगुना था। स्टॉलिपिन सुधारों (1905-11) के बाद कम्यून की स्वैच्छिक समाप्ति और संयुक्त भूमि स्वामित्वों और कर अदायगी की संयुक्त ज़िम्मेदारी के उन्मूलन से श्रम बल में तेज़ी से वृद्धि हुई और किसानों की वास्तविक आय में बढ़ोत्तरी हुई। उनके द्वारा औद्योगिक वस्तुओं की खरीददारी से यह परिलक्षित होता है कि भारी उद्योगों की अपेक्षा हल्के उद्योगों में मुनाफे की औसत दर ज़्यादा थी।

8.10.4 1914 में रूस

रूस के युद्ध में शामिल होने से पहले वर्ष जब तक सैन्य टकराव शुरू नहीं हुए थे, जिसने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया, रूस मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था। लगभग 85% लोग गाँवों में रहते थे और कृषि पर आश्रित थे। कृषि में लगभग 67% लोग रोज़गार करते थे और इससे 70% से भी ज़्यादा राष्ट्रीय आय होती थी और रूस के पिछड़ेपन, निर्धनता और अज्ञानता का भार भी अनिवार्यतः रूस के किसानों को ही झेलना पड़ता था।

गोल्ड स्मिथ का अनुमान है कि 1860 से 1913 के बीच सकल औद्योगिक उत्पादन प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ा (कारखाने और शिल्प उद्योग को शामिल करके) और प्रतिव्यक्ति उत्पादन में लगभग 3.5% की वृद्धि हुई। उस समय लगभग 50 वर्षों तक वृद्धि की इस ऊँची दर को बनाए रखना कठिन कार्य था। हालांकि रूस की आर्थिक मज़बूती का आधार कृषि मज़बूती ही रही। कृषि वह आर्थिक क्षेत्र था जहाँ न तो पर्याप्त राज्य और देशी पूँजी लगाई गई और न ही प्रमुख प्रौद्योगिकियों और अन्य विधियों का इस्तेमाल हुआ।

1914 तक रूस में औद्योगिक क्षेत्र बड़े रूप में मौजूद था। यह औपनिवेशिक या समकालीन अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के समान केवल एक 'परिक्षेत्र' नहीं था। यह बाज़ार और राजकोषीय प्रणालियों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। वस्तुतः रूस में 'दुहरा' औद्योगिक क्षेत्र था जिसमें बड़े कारखाने और उत्पादन के छोटे किसान तथा शिल्पी संगठन भी शामिल थे। रूसी अर्थशास्त्री एस. जी. स्तुरमिलिन के अनुसार यहाँ तक कि 1890 के दशक तक भी छोटे औद्योगिक उत्पादन का मूल्य दोगुना हो गया जबकि बड़े पैमाने के उत्पादन में तीन गुनी वृद्धि हुई। इस दुहरे औद्योगिक क्षेत्र में ग्रामीण आधारित विनिर्माण उत्पादन का अनुपात ज़्यादा रहना आर्थिक पिछड़ेपन को ही दर्शाता है। अन्तरराष्ट्रीय तुलना में रूस अभी भी एक अल्प विकसित देश था जो आर्थिक पिछड़ेपन का एक और संकेतक था। आर्थिक विकास की दर मापने का सबसे सरल आधार प्रति व्यक्ति आय थी। 1913 में यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन सबसे विकसित

औद्योगिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थीं। उस समय रूस की प्रतिव्यक्ति आय इन देशों की तुलना में एक तिहाई थी। जर्मनी रूस का आर्थिक आदर्श, उदाहरण और प्रतिद्वंदी था। इसकी तुलना में रूस की प्रतिव्यक्ति आय आधी थी।

बोध प्रश्न 4

1) देर से औद्योगीकरण की शुरुआत की क्षतिपूर्ति के लिए विट ने क्या रणनीति अपनाई?

....

....

....

....

2) 1890 के दशक के औद्योगिक उछाल की क्या सीमाएं थीं?

....

....

....

....

....

3) बीसवीं शताब्दी के आरंभ में औद्योगिक संकट का सामना करने के लिए सिंडिकेटों ने क्या कदम उठाए?

....

....

....

....

....

4) 1914 तक रूसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं?

....

....

....

....

....

8.11 सारांश

इस इकाई में हमने यूरोप में 1851 से 1914 के बीच औद्योगिक पूँजीवाद के विकास की चर्चा की। औद्योगीकरण की प्रक्रिया में राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके लिए राज्य ने मज़दूर उपलब्ध कराए, एक समान कानून बनाए, उद्योगों को पूँजी उपलब्ध कराई तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए बाज़ार उपलब्ध कराए। रूस जहाँ औद्योगीकरण देरी से प्रारंभ हुआ उसको यूरोप के अन्य देशों के अनुभव का लाभ मिला। रूस में उपभोक्ता वस्तुओं के सीमित बाज़ार होने के कारण भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया।

8.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) भाग 8.2 देखें। आप इसमें बैंक तथा साख की सुविधाओं का उल्लेख कर सकते हैं।

2) भाग 8.3 देखें। आप इसमें अल्जास और लारेन के जर्मनी के अधिकार में जाने के बाद भी उद्योगों ने सीमा पार से संबंध बनाए, इसके बारे में बता सकते हैं।

बोध प्रश्न 2

1) भाग 8.4 देखें

2) भाग 8.5 देखें

बोध प्रश्न 3

1) भाग 8.7 देखें

2) भाग 8.8 देखें

बोध प्रश्न 4

1) देखिए भाग 8.9

2) देखिए भाग 8.9

3) देखिए भाग 8.10

4) देखिए भाग 8.10

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY